दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 03.05.2024

रि.या.(सि) 7402/2015

समपहत संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणयाचिकाकर्ता

द्वारा: कें.स.व.अ. सुश्री निधि रमन सह
अधिवक्तागण श्री जुबिन सिंह
और श्री आकाश मिश्रा

बनाम

शैलेंद्र कुमार और अन्य प्रत्यर्थी

द्वारा: प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ
अधिवक्ता श्री कुंवर ए.के. सिंह

कोरम:

**माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा पल्ली
माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ बनर्जी**

न्या. रेखा पल्ली, (मौखिक)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन वर्तमान रिट याचिका मू.आ. सं. 2805/2013 में विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा

पारित दिनांक 13.05.2015 के आदेश पर आक्षेप करने का प्रयास करती है। विवादित आदेश के माध्यम से, विद्वत न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थियों को जारी किए गए दिनांक 16.02.2012 के आरोप ज्ञापन को दिनांक 11.04.2012 की जांच रिपोर्ट के साथ-साथ अनुशासनात्मक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण और समीक्षा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों सहित सभी परिणामी आदेशों को भी रद्द कर दिया है।

2. प्रत्यर्थियों का मामला, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित किया गया था, यह था कि उन्हें याचिकाकर्ता संगठन में आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था। जब वे एक आशुलिपिक (ग्रेड II) के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें निम्नलिखित आरोप पर दिनांक 16.02.2012 को एक आरोप ज्ञापन जारी किया गया था:

“यह कि श्री शैलेंद्र कुमार, ज्वत् संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-II एक आदतन और बाध्यकारी अनुपस्थिति है और कार्यालय में उपस्थित होने में अत्यधिक अनियमित है, अतीत में सलाह और यहां तक कि चेतावनी के बावजूद, श्री शैलेंद्र कुमार छुट्टी की अग्रिम मंजूरी या अपने नियंत्रक अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना कई दिनों तक कार्यालय से अनुपस्थिति रहे हैं। हाल ही में, कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने की उनकी प्रवृत्ति सभी सीमाओं को पार कर गई है, इस प्रकार, नवंबर, 2011 के महीने में, वह 14 नवंबर को अनुपस्थिति थे (जिसके लिए अभिलेख पर कोई छुट्टी आवेदन भी नहीं है) और फिर 18 नवंबर से 24 नवंबर तक, जिसके लिए छुट्टी आवेदन केवल नवंबर 25 पर जमा किया गया था। इसी तरह, दिसंबर 2011 के दौरान, वह 1,2,7,8,13,14,15,16,20,28 और 29 दिसंबर को बिना किसी पूर्व अनुमति के अनुपस्थिति थे। 20, 21 और 22 दिसंबर को उनकी अनुपस्थिति के लिए अभिलेख पर कोई आवेदन भी नहीं है, जबकि 11

दिसंबर को अन्य दिनों में अपनी अनुपस्थिति के लिए, उन्होंने अपनी इच्छानुसार छुट्टी का लाभ उठाने के बाद छुट्टी के आवेदनों को हटा दिया। इसी तरह, जनवरी 2012 के महीने में, वह बिना किसी छुट्टी की पूर्व मंजूरी के जनवरी, 20,23,24,25 और 27 को अनुपस्थिति थे। फरवरी के महीने में भी वे 1,3,7,8,9 और 14 फरवरी को कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहे हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पहले भी श्री शैलेंद्र कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी जिसके कारण उन पर मामूली जुर्माना लगाया गया था। इस प्रकार, श्री शैलेंद्र कुमार का उपरोक्त आचरण कर्तव्य के प्रति समर्पण की पूर्ण कमी को दर्शाता है और एक सरकारी कर्मचारी के लिए अत्यधिक अशोभनीय है और इस प्रकार सी.सी.एस. (आचरण) नियमों के नियम 3 (1) (2) और 3 (1) (3) का उल्लंघन करता है।”

3. अभिलेख के अनुसार, भले ही दस्तावेजों की एक सूची, जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों के विरुद्ध आरोप साबित करने का प्रस्ताव किया गया था, आरोप जापन के संलग्नक ग के रूप में संलग्न किया गया था, गवाहों की सूची, जो आरोप जापन के संलग्नक घ थी, में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी गवाह की जांच करने का प्रस्ताव नहीं था और गवाहों की सूची के कॉलम में "शून्य" लिखा गया था। प्रत्यर्थी यह का कहना था कि आरोप जापन की प्राप्ति पर, उन्होंने दिनांक 14.03.2012 का एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें याचिकाकर्ता से उस अवधि को माफ करने का अनुरोध किया गया था जिसके दौरान वह अपनी मनोरोग बीमारी के कारण ड्यूटी से अनुपस्थिति रहे और यह भी प्रार्थना की कि छुट्टी आवेदन जमा करने में उनकी ओर से देरी को माफ कर दिया जाए। इस जवाब को संतोषजनक नहीं पाते हुए याचिकाकर्ता ने एक जांच अधिकारी नियुक्त किया। जाँच में, हालाँकि प्रत्यर्थी ने किसी भी दुर्व्यवहार

से इनकार किया और समझाया कि उसे अपनी चिकित्सा समस्याओं के कारण बार-बार छुट्टी लेनी पड़ी, जाँच अधिकारी ने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा दायर दस्तावेजों को आधार बनाते हुए प्रत्यर्थी को आरोप का दोषी ठहराया।

4. 11.04.2012 की इस जांच रिपोर्ट को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसके परिणामस्वरूप 04.05.2012 के एक आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी पर बर्खास्तगी का जुर्माना लगाया गया था। पीड़ित होने के कारण, प्रत्यर्थी ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। समीक्षा प्राधिकरण के समक्ष भी उनकी याचिका का वही परिणाम हुआ। इसके बाद प्रत्यर्थी ने उपरोक्त मू.आ. के माध्यम से विद्वत न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसे विवादित आदेश के अधीन अनुमति दी गई है।

5. इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई है। याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश पूरी तरह से विकृत है क्योंकि विद्वान न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा है कि चूंकि प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया था कि वह काम से अनुपस्थिति रहा था, इसलिए जांच में जिन दस्तावेजों को आधार बनाया गया था, उन्हें साबित करने के लिए एक गवाह पेश करने की आवश्यकता को माफ कर दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आरोप ज्ञापन के जवाब की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, वह प्रस्तुत करती है कि किसी भी गवाह से

पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रत्यर्थी ने खुद स्वीकार किया था कि वह अनधिकृत छुट्टी पर रहा था; उसके जवाब में उसका एकमात्र अनुरोध था कि छुट्टी आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया जाए। वैकल्पिक रूप से, वह प्रस्तुत करती है कि भले ही कार्यवाही सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम 1965 के नियम 14 के अधीन भ्रष्ट पाई गई हो, लेकिन विद्वत न्यायाधिकरण को याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से रोकने के बजाय प्रत्यर्थी के विरुद्ध नए सिरे से जांच करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए थी। इसलिए वह प्रार्थना करती है कि विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाए।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता विवादित आदेश का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की याचिका कि प्रत्यर्थी ने आरोप स्वीकार किया था, पूर्ण रूप से गलत है। वह प्रस्तुत करता है कि आरोप पत्र में किसी गवाह का नाम नहीं था और इसलिए, याचिकाकर्ता की याचिका कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के कारण जांच में किसी भी गवाह से पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पूरी तरह से गलत थी। वे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि आरोप वर्ष 2012 से संबंधित है और दस साल पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए प्रत्यर्थी को इस विलंबित चरण में किसी नए सिरे से विभागीय जांच के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

7. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि यह एक सुस्पष्ट स्थिति है कि याचिकाकर्ता द्वारा जांच में पेश किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने/साबित करने के लिए किसी भी गवाह का हवाला नहीं दिया गया था। हालाँकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार आग्रह किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा अनधिकृत अवकाश पर रहने की स्वीकारोक्ति के कारण, उन दस्तावेजों को पेश और साबित करने के लिए, जिनको जांच का आधार बनाया गया था, गवाहों का परीक्षण व्यर्थ होता। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर को पढ़ने के बाद, हम इस याचिका को प्रतिग्रहण करने में असमर्थ हैं। हम सबसे पहले ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में, उसने केवल अपनी अनुपस्थिति के कारणों को समझाया था, जो उसके अनुसार उसकी मनोवैज्ञानिक बीमारी के कारण था और प्रत्यर्थी के रूप में भी, हम पाते हैं, कहीं भी किसी भी कदाचार को स्वीकार नहीं किया था। दूसरा, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा आरोप ज्ञापन का जवाब प्रस्तुत किए जाने से पहले ही, याचिकाकर्ता ने आरोप ज्ञापन के संलग्नक घ में पहले ही घोषणा कर दी थी कि किसी भी गवाह से पूछताछ करने का प्रस्ताव नहीं था।

8. हमारे सुविचारित विचार में, विद्वत न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत करने और साबित करने के लिए जांच में गवाहों को पेश करना आवश्यक है, जो गवाह प्रत्यर्थी से जिरह कर सकते थे। प्रत्यर्थी को किसी भी गवाह से पूछताछ करने का अवसर नहीं

देकर, याचिकाकर्ता ने निस्संदेह जांच में अपने आवश्यक अधिकार को कम कर दिया था। इस संबंध में हम का उल्लेख कर सकते हैं। **अनिल कुमार ध्यानी बनाम भारत संघ और अन्य (2017) एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 9911** मामले में इस न्यायालय के निर्णय, जिसमें, वर्तमान मामले की तरह, विभाग द्वारा दायर दस्तावेजों को जांच अधिकारी द्वारा आधार बनाया गया था, भले ही उन दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के लिए किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। पैराग्राफ संख्या 17 & 18 में निहित उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण नीचे पढ़े जा सकते हैं-

“17. यद्यपि यह सुस्थापित है कि घरेलू जांच में, साक्ष्य के सख्त नियम लागू नहीं होते हैं और जांच अधिकारी से न्यायालय के न्यायाधीश की तरह निर्णय लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन यह भी समान रूप से सुस्थापित प्रस्ताव है कि घरेलू जांच एक अर्ध न्यायिक कार्यवाही है और जांच अधिकारी, इस अर्ध न्यायिक कार्य को करते समय, अपने सामने रखे गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने का कर्तव्य रखता है और वह केवल अपचारी कर्मचारी को दोषी ठहराने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा दायर दस्तावेजों को आधार नहीं बना सकता है। जाँच अधिकारी द्वारा तथ्यों पर निष्कर्ष कुछ साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उससे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि कम से कम प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, यह मानने के लिए पर्याप्त है कि आरोप साबित हो गया है।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से उन दस्तावेजों से इनकार किया था जिन को प्रत्यर्थियों ने आधार बनाया था, और उसने बार-बार मूल दस्तावेजों को पेश करने का अनुरोध किया था, ताकि वह उन दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार कर सके जिन को आधार बनाया गया था। यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र में जिस दस्तावेजी साक्ष्य को आधार बनाया गया था, उसे याचिकाकर्ता कर्मचारी

द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, हमारे सुविचारित राय में, प्रत्यर्थी प्रबंधन के लिए यह अनिवार्य था कि वह उन दस्तावेजों को जांच अधिकारी के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए कम से कम कुछ गवाहों का परीक्षण करे और केवल तभी जब दस्तावेज किसी गवाह के माध्यम से जांच अधिकारी के समक्ष प्रदर्शित किया जाए और अभियुक्त अधिकारी को गवाह से जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए, तभी याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के लिए उसे आधार बनाया जा सकता है।”

9. इस संबंध में, **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक अन्य अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय। (2009) 1 एस.सी.सी. (एल.एस.) 398** के निर्णय का उल्लेख करना भी उचित होगा, जिसको विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा आधार बनाया गया था। पैरा सं. 10 में निहित उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पढ़ा जा सकता है-

“10. निर्विवाद रूप से, विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। पूछताछ अधिकारी अर्ध न्यायिक कार्य करता है। अपचारी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप साबित होने चाहिए। जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जाँच अधिकारी द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जाँच के दौरान एकत्र किए गए कथित साक्ष्य को अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सका। उक्त दस्तावेजों को साबित करने के लिए किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। प्रबंधन गवाहों ने केवल दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और इसकी सामग्री को साबित नहीं किया। अन्य बातों के साथ साथ, आधार, जाँच अधिकारी द्वारा प्राथमिकी पर रखा गया था जिसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता था। हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि पूछताछ अधिकारी द्वारा जिस एकमात्र बुनियादी साक्ष्य को आधार बनाया गया है, वह अपीलकर्ता द्वारा पुलिस के समक्ष किया गया कथित स्वीकारोक्ति था। अपीलकर्ता के अनुसार, उसे उक्त स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन में प्रताड़ित किया गया था। अपीलकर्ता के बैंक का कर्मचारी होने के कारण उक्त स्वीकारोक्ति साबित हो जानी

चाहिए थी। यह दिखाने के लिए कुछ सबूत अभिलेख पर लाए जाने चाहिए थे कि वह बैंक ड्राफ्ट बुक की चोरी में शामिल था। मान लीजिए, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। यहां तक कि कोई अप्रत्यक्ष सबूत भी नहीं था। रिपोर्ट की अवधि दर्शाती है कि पूछताछ अधिकारी ने उसे दोषी ठहराने का मन बना लिया था अन्यथा वह इस आधार पर आगे नहीं बढ़ता कि अपराध इस तरह से किया गया था कि कोई सबूत नहीं बचा था।”

10. उपरोक्त के आलोक में, हमारा विचार है कि विद्वत न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों के नियम 14 का पालन न करने के कारण जांच को भ्रष्ट किया गया था। इसलिए, हम विद्वत न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

11. अब याचिकाकर्ता की दूसरी याचिका पर आते हुए कि भले ही विभागीय जांच सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भंग होने के कारण भ्रष्ट पाई गई हो, याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही को फिर से खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रत्यर्थी ने जोरदार आग्रह किया है कि इस विलंबित चरण में याचिकाकर्ता को ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसे याचिकाकर्ता का दावा है कि पहले से उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा से आसानी से साबित किया जा सकता है, याचिकाकर्ता को नए सिरे से जांच करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। प्रत्यर्थी के अपने इस रुख को देखते हुए कि वह अनधिकृत छुट्टी पर रहा था और निजी डॉक्टरों से इलाज

करा रहा था, विद्वान न्यायाधिकरण ने उसकी सरल दलील कि उसके कर्तव्य से अनुपस्थिति रहने के लिए मजबूर करने वाले कारण थे को स्वीकार करने में गलती की।

12. उपरोक्त के आलोक में, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध नए सिरे से जांच करने के याचिकाकर्ता के अधिकार को कम करने का कोई औचित्य नहीं था। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम प्रत्यर्थी के विरुद्ध विभागीय जांच को फिर से खोलने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए राजी हैं।

13. इसलिए, हम याचिकाकर्ता को केवल 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ सेवा में बहाल करके प्रत्यर्थी के विरुद्ध नए सिरे से जांच करने की स्वतंत्रता प्रदान करके विवादित आदेश को संशोधित करते हैं, जबकि विवादित आदेश के अधीन पूर्ण पिछले वेतन का निर्देश दिया गया था। यदि याचिकाकर्ता नए सिरे से जांच करने का निर्णय लेता है, तो वह प्रत्यर्थी को उन गवाहों की सूची प्रस्तुत करेगा जिन्हें याचिकाकर्ता आरोपों को साबित करने के लिए, यदि कोई हो, पेश करना चाहता है और उसके बाद कानून के अनुसार जांच अधिकारी के समक्ष अपने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। इसके बाद जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमों के नियम 14 के सख्त अनुपालन में की जाएगी।

14. रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों के अधीन किया जाता है।

(रेखा पल्ली)
न्यायमूर्ति

(सौरभ बनर्जी)
न्यायमूर्ति

3 मई, 2024/एसओ

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।